

पटना में दिनांक-25 सितम्बर, 2019 बुधवार को अपराह्न 6:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री बागवानी मेशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6225.865 लाख (बासठ करोड़ पच्चीस लाख छियासी हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

ग्रामीण कार्य विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को अधिसूचना संख्या-3656 सह-पठित ज्ञापांक-3657 दिनांक -15.12.2016 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर अवनति की अधिरोपित शास्ति को निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत पूर्व गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-5 के उपनियम (7) के परंतुक के पश्चात् दो नये उपनियम क्रमशः (8) एवं (9) निम्नवत् जोड़े जाने हेतु बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 गठित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

पंचायती राज विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | राज्य के 24 जिला मुख्यालयों में ₹123.5496 करोड़ (एक अरब तेईस करोड़ चौवन लाख छियानवें हजार रुपये) मात्र की लागत से जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) भवन के निर्माण एवं शेष 14 अपेक्षाकृत छोटे जिलों में प्रति भवन 4 करोड़ (चार करोड़) से कम लागत का जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के निर्माण की स्वीकृति। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

भवन निर्माण विभाग

6. वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक-31.03.2020 तक) में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवनों (राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं वर्ष 2010) के बाद बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधरभूत संरचना निगम लि० (BMSICL) द्वारा निर्मित भवनों को छोड़कर) का अनुरक्षण एवं रख-रखाव से संबंधित कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में।
6. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. सुपौल जिलान्तर्गत बसंतपुर अंचल के मौजा-बसंतपुर, थाना नं०-06, खाता नं०-440, खेसरा नं०-591 न०, रकबा-0.10 एकड़ (दस डिसमिल) कोशी योजना, बिहार सरकार की भूमि को आई०बी० (Intelligence Bureau) पोस्ट, वीरपुर के कार्यालय/आवास भवन निर्माण हेतु 35,000/- (पैंतीस हजार) रू० मात्र प्रति डिसमिल की दर से 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रू० मात्र सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 4,37,500/- (चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ) रू० मात्र पूँजीकृत मूल्य सहित कुल- 7,87,500/- (सात लाख सतासी हजार पांच सौ) रू० मात्र के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।
7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. वर्ष 2020 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियबुल इन्स्ट्रुमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा।
8. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. बिहार लोक सेवा आयोग-कार्यालय के लिए सहायक निदेशक, सांख्यिकी का 01 (एक) पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में।
9. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

10. "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 2019" के गठन एवं तत्संबंधी नियमावली-प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

12. बेहतर पुलिसिंग के निमित्त बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के 43 पुलिस अनुमंडलों में अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के 43 (तीतालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

निगरानी विभाग

13. विशेष निगरानी इकाई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त अनुबंध पर नियुक्त श्री अरुण कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक की सेवा अवधि कार्यहित में दिनांक 11.05.2019 से दिनांक 10.05.2021 (70 वर्ष की आयु तक) तक विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में।
13. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

14. भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत GATE Score के आधार पर संविदा नियोजित कुल 44 (चौबालीस) सहायक अभियंता (असैनिक) की नियोजन अवधि को अगले 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति।
14. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

15. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत "जल-जीवन-हरियाली अभियान" के क्रियान्वयन हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 100 (एक सौ) करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति के संबंध में।
15. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

16. "जवाहर लाल नेहरू मार्ग" का नामकरण "नेहरू पथ" किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
16. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

17. जल-जीवन-हरियाली अभियान के संचालन एवं इस पर होने वाले ₹24524.00 करोड़ (दो खरब पैतालीस अरब चौबीस करोड़) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति एवं लक्ष्यों के निर्धारण, नियमित अनुश्रवण एवं अभियान को मिशन मोड में लागू करने के लिए जल-जीवन-हरियाली मिशन के गठन की स्वीकृति तथा इस पर होने वाले ₹23.39 करोड़ (तेईस करोड़ उनचालीस लाख) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
17. स्वीकृत।